

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2—अनुभाग 3क
PART II— Section 3A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10 No. 10 नई दिल्ली, सोमवार, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक)
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2013/SHRAVANA 21, 1935 (SAKA)

खण्ड XLIV Vol. XLIV

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खंड

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2013/21 श्रावण, 1935 (शक)

दि अंदमान एंड निकोबार आइलैंड्स (प्रोटेक्शन आफ एबोरिजनल ट्राइब्स) अमेंडमेंट रेग्युलेशन, 2012 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT) OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, August 12, 2013/Shravana 21, 1935 (Saka)

The translation in Hindi of the Andaman and Nicobar Islands (Protection of Aboriginal Tribes) Amendment Regulation, 2012 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

भारत सरकार

## गृह मंत्रालय

## अंदमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जनजाति संरक्षण) संशोधन विनियम, 2012

(2012 का विनियम संख्यांक 2)

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रपित द्वारा निम्निलिखित रूप में प्रख्यापित। अंदमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए विनियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 240 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए निम्निलिखित विनियम को प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम अंदमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जनजाति संरक्षण) संशोधन विनियम, 2012
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- 2. धारा 2 का संशोधन—अंदमान और निकोबार द्वीप (आदिवासी जनजाति संरक्षण) विनियम, 1956 (1956 का विनियम सं० 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—
  - (i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(कक) "विज्ञापन" के अन्तर्गत ऐसी कोई सूचना, परिपन्न, लेबल, आवेष्टन या कोई अन्य दस्तावेज या किसी प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से या इलैक्ट्रानिकी पारेषण के माध्यम से दृश्य प्रतिनिधित्व या उद्घोषणा या श्रव्य या दृश्य पारेषण है;

(कख) "मध्यवर्ती अंचल" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो आरक्षित क्षेत्र से लगा हुआ और संलग्न है और जो धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक द्वारा उस रूप में अधिसूचित किया गया है ;';

(ii) खंड (ख्र) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

- '(खक) "वाणिज्यिक स्थापन" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जो कोई व्यापार या कारबार करता है या प्रतिफल के लिए सेवाएं देता है और जिसके बीस से अधिक कर्मचारी हैं या जिसका एक करोड़ रुपए या उससे अधिक वार्षिक आवर्त है ;';
- (iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थातु :—
  - '(ग) "उपायुक्त" से, अंदमान और निकोबार द्वीप के, यथास्थिति, दक्षिणी अंदमान या उत्तरी और मध्य अंदमान जिले या निकोबार का उपायुक्त अभिप्रेत है;
  - (गक) "कर्मचारी" से वाणिज्यिक स्थापन या पर्यटन स्थापन के संबंध में मजदूरी, वेतन पर या कमीशन के आधार पर किसी अविध के लिए नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसमें नियोक्ता के कुटुंब का कोई सदस्य सिम्मिलित नहीं है;";
- (iv) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
  - '(छ) "पर्यटन स्थापन" से केन्द्रीय सरकार या अंदमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के अतिथि गृहों के सिवाय रिसोर्ट, होटल, रेस्तरां, बार, आश्रय या खान-पान गृह, कैफे, पेइंग गेस्ट आवास या ऐसे अन्य स्थान अभिप्रेत हैं।'।

3. नई धारा 3क का अंत:स्थापन—मूल विनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"3क. मध्यवर्ती क्षेत्र की घोषणा—(1) जहां प्रशासक की यह राय है कि आरिक्षित क्षेत्र में रह रही आदिवासी जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यंक है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को, जो आरिक्षत क्षेत्र से लगा हुआ और संलग्न है, मध्यवर्ती अंचल के रूप में घोषित कर सकेगा और ऐसे क्षेत्र की परिसीमाओं को समय-समय पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा, और उसी रीति में ऐसी परिसीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा।

- (2) इस संबंध में कि क्या कोई क्षेत्र मध्यवर्ती अंचल में आता है या उसके बाहर है, यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय प्रशासक द्वारा किया जाएगा तथा उसका विनिश्चय अंतिम होगा।"।
- 4. नई धारा 7क का अंतः स्थापन—मूल विनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"7क. मध्यवर्ती क्षेत्र में पर्यटक या वाणिज्यिक स्थापनों के स्थापन या प्रचालन का प्रतिषेध—(1) कोई व्यक्ति मध्यवर्ती अंचल में पर्यटक स्थापन या वाणिज्यिक स्थापन की स्थापना या प्रचालन नहीं करेगा।

- (2) कोई व्यक्ति आदिवासी जनजातियों से संबंधित विज्ञापन द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटक गतिविधियों का संवर्धन नहीं करेगा।"।
- 5. धारा 8 का संशोधन—मूल विनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्निलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
  - "(4) जो कोई धारा 7 के अधीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में आदिवासी जनजातियों का फोटो लेने या वीडियो बनाने के प्रयोजन के लिए आरिक्षत क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
  - (5) जो कोई, धारा 7 के अधीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में उक्त क्षेत्र में अतिलंघन, शिकार या शिकार चोरी के प्रयोजन के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

- (6) जो कोई, धारा 7 के अधीन जारी अधिसूचना के उल्लंघन में आरिक्षित क्षेत्र में, किसी भी रूप में ऐल्कोहल या अत्यंत ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ का कोई रूप या जैविक कीटाणु, जीवाणु, विषाणु का कोई रूप किसी आदिवासी को देने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करेगा, वह कारावास से, जो सात वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।"।
- 6. नई धाराओं 8क, 8ख और 8ग का अंत:स्थापन—मूल विनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्निलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'8क. मध्यवर्ती अंचल में पर्यटन या वाणिज्यिक स्थापनों की स्थापना के लिए दंड—जो कोई धारा 7क की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, मध्यवर्ती अंचल में कोई पर्यटन स्थापन या वाणिज्यिक स्थापन की स्थापना या प्रचालन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

8ख. आदिवासी जनजातियों से संबंधित विज्ञापन द्वारा पर्यटन का संवर्धन करने के लिए दंड—जो कोई धारा 7क की उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासी जनजातियों से संबंधित विज्ञापन द्वारा पर्यटन गतिविधियों का संवर्धन करेगा, वह कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा तथा जुर्माने से, जो दस हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

8ग. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस विनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस विनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह कंपनी किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया था या उस अपराध का किया जाना उस समय उसकी उपेक्षा के कारण तब माना जा सकता है जब अपराध किया जाता है या किया गया था, तो ऐसा व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यष्टियों का कोई अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।'।

> रामावतार यादव, उप विधायी परामर्शी, भारत सरकार।